

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.5131नवि/99पार्ट

जयपुर, दिनांक:- 6.7.2002

-आदेश-

नगर विकास न्यासों, स्थानीय निकायों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि भूमि पर ऐसी अनैक आवासीय योजनाएं विकसित हो गई हैं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गये हैं किन्तु आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित प्लॉट्स का पालन नहीं किया है। ऐसे निर्माण सड़क सीमा एवं सुविधा क्षेत्र में कर दिये गये हैं। स्थानीय निकाय एवं नगर विकास न्यास इन निर्माणों को ध्वस्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं किन्तु नगर निगमों के निर्धारित प्लॉट्स का अधिक उल्लंघन करना भी उचित नहीं है। इस समस्या के मानवीय पहलू को देखते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक-प.5131नवि/99पार्ट दिनांक 11-1-2002 के द्वारा आवासीय एवं स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सुविधा क्षेत्र के लिए स्वीकृत प्लॉट्स में 5 प्रतिशत सिविल का अधिकार जोन कमेटी को दिया गया है। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत नगर विकास न्यासों एवं स्थानीय निकायों को उनी अनुसार स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए ऐसी आवासीय योजनाएं जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है, में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधा क्षेत्र के लिए निर्धारित प्लॉट्स में 5 प्रतिशत सिविल करने का अधिकार प्रदान किया जाता है।

आज्ञा है,

[स.स.भारदार]

उपमहानगर सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए:-

1. सचिव, ना. कुलकर्णी स्पोर्ट्स, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव भा. स्त्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. संभागीय आयुक्त, तमस्त/जिला जेकर, तमस्त।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज. जयपुर को भेजकर देना है कि नगरीय नगर-परिषदों/नगरपालिकाओं को अपने स्तर से सुविधा करने का पालन करें।
8. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास समिति, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार जयपुर।

(15)

उपमहानगर सचिव